रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2016/अग्रहायण 17, 1938
No. 365] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2016/AGRAHAYANA 17, 1938

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2016

फा.सं. एन-11018/8/2014-यूएसडी(खंड-V)एफटीएस 16910. – शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार के संबंध में, 2003 की रिट याचिका (सिविल) सं. 55 और 2003 की रिट याचिका (सिविल) सं. 572 में माननीय उच्चतम न्यायालय की दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नवत करती है :-

1. माननीय न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर,
   भूतपूर्व न्यायधीश दिल्ली उच्च न्यायालय - अध्यक्ष
2. श्री नीरज कुमार गुप्ता,
   सेवा निवृत अधिकारी, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा - सदस्य सचिव
3. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव
   आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय - सदस्य
   भारत सरकार द्वारा यथा प्रतिनियुक्ति

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के आदेशानुसार, समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा :

(i) समिति प्रत्येक शहर/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी बेघरों के लिए उपलब्ध आश्रयों का भौतिक सत्यापन करेगी ।

(ii) यह भी सत्यापन करेगी कि क्या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्कीम हेतु प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(iii) समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आश्रय गृहों की स्थापना करने में धीमी प्रगति के कारणों की जांच करेगी ।

(iv) समिति इसके अलावा, शहरी बेघरों को आश्रय मुहैया कराने के लिए स्कीम हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं करने और/अथवा विवर्जन/दुरूपयोग के बारे में जांच करेगी ।

(v) समिति यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समुचित सिफारिशें करेगी कि शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए सर्द ऋतु के दौरान उनकी रक्षा करने हेतु कम से कम अस्थायी आवास मुहैया कराए जाएं । राज्य सरकारें समिति द्वारा उल्लिखित समय सीमा सहित सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी । कोई कार्यान्वयन न होने संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा ।

3. समिति 4 महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2016

F.No. N-11018/8/2014-USD(Vol-V) fts 16910.—In pursuance of the Order dated 11th November, 2016 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition(Civil) No. 55 of 2003 and Writ Petition(Civil) No.572 of 2003 , relating to rights to shelter of homeless persons in urban areas, the Central Government hereby constitutes a three Member Committee as follows:

1. Hon'ble Justice Kailash Gambhir - Chairman
   Former Judge of the High Court of Delhi
2. Mr. Neeraj Kumar Gupta - Member Secretary
   Retired officer of Delhi Higher Judicial Service
3. Shri Sanjay Kumar, Joint Secretary,
   Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation - Member
   as deputed by the Government of India

2. As per the Order dated 11th November 2016 of the Hon'ble Supreme Court, the scope of work of the Committee shall be as follows:

(i) The Committee shall cause physical verification of the available shelters for urban homeless in each state / UT.

(ii) The Committee shall also verify whether the shelters are in compliance with the operational guidelines for the scheme of Shelters for Urban Homeless under the National Urban Livelihood Mission (NULM).

(iii) The Committee shall enquire into the reasons of the slow progress in setting up of shelter homes by the States / UTs.

(iv) The Committee shall further enquire about non-utilization and / or diversion / misutilisation of the funds allocated for the Scheme for providing shelters to the urban homeless.

(v) The Committee shall issue suitable recommendations to the State Governments to ensure that at least temporary shelters are provided for the homeless in the urban areas to protect them during the winter season. The State Governments shall ensure compliance with the recommendations along the timeframe indicated by the Committee. Any non-implementation shall be drawn to the attention of the Supreme Court.

3. The Committee shall submit its report within a period of four months.

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.12.08 13:03:13 +05'30'